

कैपिटल ज़ोन



उत्पात

एक्सप्रेस वे पर अंडरपास का काम पूरा

नोएडा, 3 सितम्बर (देशबन्धु)। नोएडा-प्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर सेक्टर-96 और 126 के बीच बन रहे अंडरपास का निर्माण पूरा हो गया है। अब सिफर रंगीन-पूर्व और बाहन गुजार कर देखे जाने हैं। प्रॉजेक्ट से जुड़े इंजीनियरों का कहना है कि 15 दिन के अंदर ये काम पूरे करवाकर अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। जून-2020 में इस अंडरपास का निर्माण शुरू हुआ था। ये अंडरपास खुल जाने से आस-पास के 14 सेक्टरों में निवासियों का आवासमन आसान होगा। एक्सप्रेस-वे पर इसके पहले कोंडली और एडवर्ट अंडरपास भी अर्थारिटी बनाकर खोल चुकी है। करीब 96 करोड़ रुपए की लागत से यह अंडरपास बांक्स पुशिंग तकनीक से बनाया जाना था। ऐसा होने पर एक्सप्रेस-वे की ऊपर ट्रैफिक चलने के कंक्रीट के बांक्स मरीन से मिट्टी की कटाई कर रख दिए जाते। यही डीपीआर भी तैयार हुई थी। जनवरी-2023 तक काम भी इसी तकनीक पर चला। लेकिन आखिरी में इंजीनियरों ने विशेष मंजूरी लेकर इस अंडरपास का काम इकाई करवाने के लिए एक्सप्रेस-वे की सड़क भी कटवाई फिर अंडरपास का निर्माण पूरा हो पाया है। काम शुरू होने के बाद कई बार देरी भी हुई। कोविड व अन्य कारणों से बीच-बीच में काम भी रुकता रहा। अर्थारिटी ने दो बार जुमाना भी लगाया है।

सार संक्षेप

सेक्टर-3-5 आरडब्ल्यूए चुनाव में एनपी सिंह पैनल जीता

नोएडा। आरडब्ल्यूए सेक्टर-3-5 नोएडा के चुनाव संघर्ष हुए। चुनाव में एनपी सिंह पैनल ने निविरोध जीत दर्ज की। अनिल तलवार कोषाध्यक्ष, सामाजिक संघिय एमपी सिंह, केरी के त्यागी संघिय के पद पर, वालविशन दास जोयल एजन्सीस्ट्रॉय मेंबर ये सभी निविरोध जियारी हुए। इसके अलावा महासंघिय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के 3 पदों पर वोटिंग हुई। इसमें भी एनपी सिंह पैनल की ओर महासंघिय राजीव जैन ने राजीव वीरी को 4 वोटों से हाराया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष यशपाल सिंहाजा ने आर के रेणा को 12 वोटों से हाराया। उपाध्यक्ष संजीव अग्रवाल बने उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कुंदन सिंह को 19 वोटों से हाराया।

कंपनी में तोड़फोड़ करने पर दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

नोएडा। कोतवाली फेज-वन क्षेत्र के सेक्टर-दो रिटेल लीटी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से ग्रेसी बालियान ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि 18 अगस्त की शाम अमिता शर्मा और उनके भाई अंजय शर्मा कार्यालय में आए। दोनों ने सभी के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। स्टार ने विरोध किया तो हाथापाई की। शेरू सुनकर सिक्योरिटी गार्ड श्रीप्रकाश पूर्वों तो उन्हें झूठे केस में फँसाने की धमकी देते हुए जान से मारने नहीं आरोपियों ने एनपी के तोड़फोड़ करके लायों रुपए का सामान नष्ट कर दिया। अब ये लोग कंपनी को बदनाम कर रहे हैं। कोतवाली प्रभारी छव्वे दुवे का कहना है कि शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अवैध रूप से पटाखे तैयार करने वाले सात लोग गिरफ्तार करने वाले सात लोगों को खिलाफी जांच

गाजियाबाद। थाना मुरादगढ़र पुलिस टीम ने अवैध पटाखे व फायर शॉट्स तैयार करने वाले सात लोगों को खिलाफी जांच गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 261 फायर

शॉट्स (कल्ड फायर पायरो) (पूर्ण निर्मित) व 46 किलो 300 ग्राम फायर शॉट्स बनाने में प्रयोग होने वाला सफेद पाउडर व 27 किलो 500 ग्राम फायर शॉट्स बनाने में प्रयोग होने वाला पाउडर (बालू) व 13 ग्रॉमों में फायर शॉट्स बनाने वाली गर्जे की बेलनाकार बली, पटाखे बनाने के अन्य उपकरण व मरीन बरामद की रविवार को बताया कि गिरफ्तार लोगों में रिजावाल, अरिफ, हसमुद्दीन, गफार, आविद अली, निसार निवासी फर्जलूनगर तथा साहिल निवासी की गिरफ्तार होना चाहिए। शिक्षक के लिए एक्सप्रेस वे पर देखने वाले जिला भर रहे हैं।

एनपी मुरादगढ़र को रविवार को बताया कि गिरफ्तार लोगों में रिजावाल, अरिफ, हसमुद्दीन, गफार, आविद अली, निसार निवासी फर्जलूनगर तथा साहिल निवासी की गिरफ्तार होना चाहिए। शिक्षक के लिए एक्सप्रेस वे पर देखने वाले जिला भर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि ये लोग विस्फोटक तैयार करने वाले में वेष्ट हैं। इन्स्टीट्यूशन के अपने आपको सबसे बड़ा चुनाव देना चाहिए। उनके बारे में विस्तार से प्रकाश डाला।

आज से नक्शा पास करना और सीसी लेना होगा महंगा

नोएडा, 3 सितम्बर (देशबन्धु)। नोएडा प्राधिकरण से संबंधित आविटिंग संपत्ति का नक्शा पास करना और पूर्णता प्रमाण पत्र लेना आज (सोमवार) से महंगा हो जाएगा। अब नक्शा पास के लिए 30 और पूर्णता प्रमाण पत्र लेने के लिए 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फीस देनी होगी। अभी तक दोनों मामलों में यह शुल्क 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर लगता था।

12 अगस्त को नोएडा प्राधिकरण की हुई 210वीं बोर्ड द्वारा ये शुल्क बढ़ाने का नियम लिया गया था। बोर्ड बैठक अवधिकरण एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार विंग की अध्यक्षता में हुई थी। अब इकाई सोमवार से लागू होने के लिए 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फीस देनी होगी। अब घर बनाने के लिए नक्शा पास करने के लिए सभी प्रकार के भवनों के लिए सभी मैटिलों के ढक हुए क्षेत्र पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर से शुल्क देना होगा। इसके अलावा अधिकार्यास व्यापार व निवास योजना के लए 4 हेक्टेयर तक के भविंड क्षेत्र के लिए 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर और इससे बड़े एक्स्ट्रीम क्षेत्र के लिए 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फीस देनी होगी।



■ नक्शा पास करने के लिए 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर और सीसी लेना होगा महंगा

ने बताया कि नक्शा पास करने के लिए सभी प्रकार के भवनों के लिए सभी मैटिलों के ढक हुए क्षेत्र पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर से शुल्क देना होगा। इसके अलावा अधिकार्यास व्यापार व निवास योजना के लिए 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फीस देनी होगी। अब घर बनाने के लिए नक्शा पास करने के लिए सभी प्रकार के भवनों के लिए 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फीस देनी होगी।

सरकार की प्राथमिकता में है जच्चा-बच्चा की सेवा और सुरक्षा : बृजेश पाठक

गाजियाबाद, 3 सितम्बर (देशबन्धु)। उप-मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने रविवार को मुरादगढ़र में चार करोड़ की लागत से भवनों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उहोंने कहा कि बच्चा की सेवा और सुरक्षा प्राथमिकता है।

उहोंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जनता की सेवा की चिंता करते हुए लगातार गाजियाबाद सहित सम्पूर्ण 75 जिलों स्वास्थ्य सेवाओं के नियमण एवं विकास कार्यों पर प्राथमिकता से ध्यान दे रही है। उसी का असर है कि गाजियाबाद में लगातार समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, हेल्प एंड वेलनेस सेन्टरों सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बंधित भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है। पहले मामूली स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कई मैटिलों पर जापता था और बार बार जापता था।



■ उप-मुख्यमंत्री ने किया लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भवनों का उद्घाटन

सकती है और बारकोड से स्कैन होने पर सरकार उसका बिल स्वयं बहन करेंगे। इसके लिए कई लोगों पर जापता था और बार बार जापता था। गभर्वती महिलाओं के लिए एक कार्डियन डिस्ट्रिक्ट करवा रही है और बारकोड से स्कैन होने पर जापता था। गभर्वती ने कहा कि जापता था और बारकोड से स्कैन होने पर जापता था। गभर्वती ने कहा कि जापता था और बारकोड से स्कैन होने पर जापता था। गभर्वती ने कहा कि जापता था और बारकोड से स्कैन होने पर जापता था। गभर्वती ने कहा कि जापता था और बारकोड से स्कैन होने पर जापता था।

जल्द ही क्रिटिकल केयर यूनिट लगवाई जाएगी। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री जनरल वीट सिंह सासद राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल मुरादगढ़र में विधायक अंजीत पाल त्यागी ने भी संबंधित किया। इस मौके पर जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह निर्मित व्यापार केन्द्रों में अल्ट्रासाउंड मरीनों, सहित अन्य लोगों द्वारा लगातार जारी हो रही है। यहीं लोगों के लिए एक कार्डियन डिस्ट्रिक्ट करवा रही है। गभर्वती ने कहा कि जापता था और बारकोड से स्कैन होने पर जापता था। गभर्वती ने कहा कि जापता था और बारकोड से स्कैन होने पर जापता था। गभर्वती ने कहा कि जापता था और बारकोड से स्कैन होने पर जापता था। गभर्वती ने कहा कि जापता था और बारकोड से स्कैन होने पर जापता था। गभर्वती ने कहा कि जापता था और बारकोड से स्कैन होने पर जापता था।

नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने एचपीडीए के उपाध्यक्ष विक्रमादित्य मलिक के लिए निर्माण का अधिकारी दिल्ली बनाया



गाजियाबाद, 3 सितम्बर (देशबन्धु)। नगर आयुक्त डॉ. नितिन गौड़ का तबादला कर दिया गया है। उहोंने हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण (एचपीडीए) का उपाध्यक्ष बनाया। गाजियाबाद के केन्द्रीय मंत्री विक्रमादित्य मलिक को गाजियाबाद



{ संपादकीय }

नई दिल्ली, सोमवार 4 सितम्बर 2023

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

देश को संशय में डालती मोदी सरकार

संसदीय परम्पराओं की अवहेलना करने की आदी हो चुकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने अपनी इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए देश के इतिहास में पहली बार ट्रिवट के जरिये संसद का विशेष सत्र बुलाकर साबित कर दिया है कि वहन केवल गैरीजमंदार है वरन् उसका पारदर्शिता से भी कोई लेना-देना नहीं रह गया है। ऐसे बत्त में जब संयुक्त क्रिकेट का गठबन्धन 'ईडिया' (ईडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्यूजिव एलएस) मुबार्ख में 31 अगस्त व 1 सितम्बर को 2024 के लोकसभा की चुनावी रणनीति में व्यस्त था, केन्द्रीय संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह जानकारी दी कि 18 से 22 सितम्बर को विशेष सत्र होगा। भले ही इस सूचना को 'ईडिया' उपरक्षित कर अपनी कार्यवाही में लागा रहा लेकिन यह एक तरह से देश को अंधेरे में रखने जैसा है क्योंकि यह कार्यप्रणाली किसी लोकतात्रिक रूप से चुनी हुई सरकार की नहीं हो सकती। न ही यह 'ईडिया' को बढ़ती एकता के जवाब में होनी चाहिये।

इसे लेकर कई तरह के कथास हैं। इसमें वर्ष 2024 में होने जा रहे लोकसभा को समय से पहले करा लेने की सम्भावना से लेकर संविधान में संशोधन, चुनाव टाल देने या फिर मोदी को हमेशा के लिये पीएम बनाये जाने जैसी गुंजाइशें टटोली जा रही हैं। चीन द्वारा नया नक्शा जारी करना (जिसमें अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया गया है), मणिपुर हिंसा, गौतम अदानी को लेकर नये खुलासे, महंगाई आदि अनेक विषय हैं जिनके बारे में अनुमान व्यक्त किये जा रहे हैं कि इन मसलों पर सरकार कोई बात करना चाहती है। क्यों नहीं सरकार ने इन विषयों पर तब चर्चा कर ली? सबल यह भी है कि क्यों लोगों या सांसदों को विषय को लेकर कपास लगाने के लिये छोड़ा जाये? क्यों नहीं सूचना के साथ ही विषय की जानकारी दे दी गई? संसद पर केवल सत्ता का हक नहीं है, जो अन्य लोगों को इसकी सूचना से वर्चित रखा जाये। यह सत्र 5 दिनों का बयों है, जबकि विशेष सत्र एकाध दिन के होते हैं? दुर्भाय से तमाजों के आयोजनों में पारंगत मोदी सरकार इसे भी इंवेंट बना रही है।

आखिरकार विशेष सत्र कोई मजाक नहीं होता और न ही उसे सत्तापक्ष का कोई विशेषधिकार समझा जाये, बावजूद इसके कि सरकार को ऐसा करने का पूरा हक है। तो भी, इस अधिकार का प्रयोग बहुत गम्भीरों से; और बेहद खास उद्देश्यों को लेकर होना चाहिये। विशेष सत्र का विषय क्या है, यह किंविति विशेषिताओं में अधिकारित किया जा सकता है— और इसे बुलाये जाने का प्रयोग क्या है— यह सारा कुछ सरकार को बतलाना चाहिये था। यह सूचना प्रेस कॉर्फ्स के माध्यम से तथा बाकायदा एक अधिसूचना जारी करन नागरिकों को देनी थी। संसद पर पहला हक तो नागरिकों का होता है, चाहे वे स्वयं इसके प्रत्यक्ष सदस्य न हों। जो सदस्य दोनों सदनों में बैठते हैं वे अंततः जनसामान्य की ही नुमाइंदाएँ करते हैं। सरकार को पहले तो इस पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिये थी फिर अपना उद्देश्य बतलाना चाहिये था।

मोदी सरकार द्वारा संसदीय गरिमा व परम्पराओं को ध्वस्त करने की पूरी श्रृंखला है, जिसकी एक और कड़ी का सम्बन्ध इसी एपीसोड से है। सरकार ने एक समिति बनाई है जो 'एक देश एक चुनाव' की योजना बनाकर सरकार को सौंपेंगी। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सेवानिवृत राष्ट्रपति को किसी समिति का अध्यक्ष बनाकर सरकार के किसी तात्परी का प्रयोग सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है जो कभी सिर्फ उस विभाग का नहीं बरन पूरी सरकार का प्रमुख दुआ करता था। बास्तविकता में चाहे न हो लेकिन सर्वेधानिक परिभाषा के अनुसार तो वह राष्ट्रध्यक्ष ही है जिसके अधीन पूरा देश होता है। संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत खुद मोदी इन्हीं राष्ट्रपति के अंतर्गत काम कर चुके हैं। न यह कोई पूछने वाला है और नहीं कोई बताने की आयोजनों का नहीं, किसी सरकार की आयोजनों का भी नहीं, बल्कि पूरे देश की आयोजनों का पानी मर जाये।

अगर 'एक देश एक चुनाव' की बात करें तो यह करा पाना बहुत कठिन है। प्रशासनिक दोनों कारोंगों से अव्यवहारिक। आजादी के बाद हुए पहले चार अम चुनावों के साथ विधानसभाओं के निर्वाचन हुए थे परन्तु तब की परिस्थितियां अलग थीं। आबादी कम थी, चुनावी हिंसा न्यूनतम थी। राजनीतिक दलों के बीच आज के जैसी वैमनस्यता भी नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि चुनावों का आकार व स्वरूप विशाल नहीं था। इसके बावजूद अगर सरकार एक साथ चुनाव कराना ही चाहती है तो पहले वह इसके फायदे बताता यह। यह भी बताये कि सामान्य नागरिकों, विशेषकर मतदाताओं को किसी सी भी प्रकार की परेशानी में डाल बैठ ये कैसे सम्पन्न होंगे। जब मणिपुर जैसे छोटे से राज्य की हिस्सा को रोकने में सरकार 5 माह में भी सफल नहीं होती और ज्यादातर राज्यों के चुनाव कई चरणों में करने पड़ते हैं, तो इन्हें बड़े देश में एक दिन में कैसे चुनाव हो सकते हैं। यह जाने का हक नागरिकों का है, और बतलाना सरकार का कर्तव्य।

इंडिया की सफलता से बौखलाया मीडिया

30

प बायाती जानते हैं!

तो यह मीडिया आज बायाती प्रवृत्ति का हो गया है। छिद्रांचेपो !

ईडिया को बेहद सफल मुबार्ख बैठक में उसने बहुत सारी कामियां खो ली हैं। जैसे वह बायाती सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जो लड़की बालों के बायाती बनाकर यह केवल सफल सके कि उसने को काकोल में चाय बनाकर नहीं पिलाई वा पीनी पर बायाती बनाया। परीक्षा बनाया तो क्या ? चिकन बनाया तो क्या ?

बनाना तो परीक्षा चिकन का विशेष सत्र बायाती बनाया तो चाय की लड़की बालों की शारी में भी कमी निकाल सकता है। तो यही हाल अज हमारे मीडिया का हो गया है।

झंडा क्यों नहीं बनाया ? झंडा था क्या कभी इससे पहले किसी गर्वबंधन का ? जिस एनाईटो की अब यह बीजेपी की जाग चुनाव तो रहा है। क्या उसका कोई चंडी बंधा है ? या केवल विषक्षी गर्वबंधन का ही चंडी बंधा है ? सारी शर्त लड़की और लड़का पाली तो लगा है। अपने लिए तो हाल बर ना नियम बनाते रहेंगे। पहले तो केवल आएगा तो मोदी ही का माहील बना रहा थे। मगर जब आएगा तो यह मोदी को खोला रहा है। और अब जब विषक्ष एक ही गया तो ज्ञाया की बात करने लगे। 2019 के बाद कहना शुरू कर दिया था कि देश से गर्वबंधन को राजनीति खत्म हो गया। मगर जब जब ज्ञाया हो गया तो कूट बन एक एनाईटो आगे बढ़ा रहा है।

मुंबई का संदेश क्या है ? इन्डिया को लिए कि छोटी-छोटी बातें छोड़ने से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और मीडिया के लिए कि बने रहे पुछले। तुक्करी नियत हो रही है।

हालांकि इंडिया के नेताओं ने मुबार्ख पटना, बंगलुरु और मुंबई। लेप्टोप के एक नहीं तीन तीन नेता, सीपीआईएम के सातीराम ये चुरी, सीपीआई के ढी राजा और सीपीआईएमएल के दोपीकर भट्टाचार्य उनमें ममता बनर्जी के साथ मीठा रहे, खबर बातें करते हुए।

खंगीचान तो नहीं होती है ? गोदी मीडिया में नहीं होती है ? एक देश एक नहीं होता है ? गोदी मीडिया में नहीं होती है ? एक देश एक नहीं होता है ? गोदी मीडिया के नेता जो नेता कि हमारे कामों में मुंबई के लिए तक तक कब तक करता रहा है। ज्यादा से ज्यादा जहरीला बनने के लिए कुछ एक एंकर में लगता है और जहर के बीचेकर भी लगता है। पढ़ते ही, मगर यह भवित्व तो ऐसे चाहते हैं कि कमी हो जाती है। अभी एक एकर को सुनने को मिल गया कि जब जेल गए तो कैसा लगा ? अपने एयर बात हो रही थी जहर फैलाने में सबसे तेज निकल रहा एंकर बैचारा यह

को मीटिंग खत्म होते ही शिवसेना के संजय राउत ने मबासे पहले यही बताया कि अपने साथ बायाती के मंत्री नहीं कर सकते।

बायाती को बैठक की सुबह मीटिंग शुरू होने से पहले सोनीया की तारीफ की गयी थी कि लड़का उड़ाकर उनका समान करना को हिंसा बताया गया है। अभी तो कूछ रख्या

सोनीया को बैठक से बायाती को बायाती के मंत्री नहीं कर सकता।

बायाती को बैठक से बायाती को बायाती के मंत्री नहीं कर सकता।

बायाती को बैठक से बायाती को बायाती के मंत्री नहीं कर सकता।

बायाती को बैठक से बायाती को बायाती के मंत्री नहीं कर सकता।

बायाती को बैठक से बायाती को बायाती के मंत्री नहीं कर सकता।

बायाती को बैठक से बायाती को बायाती के मंत्री नहीं कर सकता।

बायाती को बैठक से बायाती को बायाती के मंत्री नहीं कर सकता।

बायाती को बैठक से बायाती को बायाती के मंत्री नहीं कर सकता।

बायाती को बैठक से बायाती को बायाती के मंत्री नहीं कर सकता।

बायाती को बैठक से बायाती को बायाती के मंत्री नहीं कर सकता।

बायाती को बैठक से बायाती को बायाती के मंत्री नहीं कर सकता।

बायाती को बैठक से बायाती को बायाती के मंत्री नहीं कर सकता।

बायाती को बैठक से बायाती को बायाती के मंत्री नहीं कर सकता।

बायाती को बैठक से बायाती को बायाती के मंत्री नहीं कर सकता।

बायाती को बैठक से बायाती को बायाती के मंत्री नहीं कर सकता।

